



2026:AHC : 22267-DB

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या- 1597 वर्ष 2020

रईस अहमद उर्फ रईसू

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता

: श्री एम. जे. अख्तर, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या – 42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. वर्तमान आपराधिक अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, बिजनौर द्वारा धारा 302/34, 326क/34, 342 और 201 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन – नजीबाबाद, जिला बिजनौर के तहत केस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



क्राइम नंबर 976/2016 से उत्पन्न मामले की संख्या 976/2016 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2. मामला 5.12.2016 को 14:50 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ शुरू किया गया था। पहले मुखबिर, अर्थात् अहमद अली @ नन्हे ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा था कि कुछ दिन पहले उसकी भांजी (बहन की बेटी) को एक पड़ोसी के बेटे से प्यार हो गया था, जो बहन फातिमा के पति रहीसा को पसंद नहीं था। भले ही मामले में समझौता हो गया था, लेकिन पहले मुखबिर की बहन का पति अपनी बेटी के साथ बहुत नाराज था और इसलिए, इस घटना के कारण, पहला मुखबिर अपनी भतीजी को काशीपुर में अपने घर ले आया था, जहां वह लगभग 4 महीने तक रही। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, यह कहा गया है कि 4.12.2016 को शाम 6:00 बजे पहले मुखबिर की बहन का पति रहीसा पहले मुखबिर के घर आया और उसे बताया कि कुछ लोग उसकी बेटी को उसके घर मसवानी में उसकी शादी के सिलसिले में देखने आ रहे हैं और इसलिए, फरहीन को उसके साथ भेजा जाए। इस अनुरोध पर पहले मुखबिर ने फरहीन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर काशीपुर के रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंचाया और वहां छोड़ दिया। अगले दिन यानी 5.12.2016 को सुबह लगभग 7:00 बजे, उन्हें नजीबाबाद अस्पताल से सूचना मिली कि उनकी भतीजी फरहीन को एसिड से जला दिया गया है और वह नानुवाला गांव में पाई गई है और आगे के इलाज के लिए उसे बिजनौर के एक बेहतर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। यह खबर मिलने पर पहला मुखबिर अपने भाई मुबारक अली के साथ बिजनौर सरकारी अस्पताल पहुंचा और अपनी भतीजी से मिला, जिसने उसे बताया कि उसके पिता और नबी हसन उसे काशीपुर रोडवेज बस स्टैंड से ले गए थे और उसे एक पिकअप वैन में बैठाकर अपने गांव के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में वह सो गई थी। भतीजी के पिता के पार्टनर नबी हसन ने उसका गला घोटने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल गई थीं और उसने सब कुछ देख लिया था। इसके बाद उसने कहा था कि उसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं पता कि क्या हुआ था। उसने यह भी बताया था कि नजीबाबाद अस्पताल से एक वाहन उसे लेने आया था। उसने पहले मुखबिर को यह भी बताया था कि उसने अस्पताल के अधिकारियों को पहले मुखबिर (नन्हे मामा) का टेलीफोन नंबर दिया था, जिन्होंने उसे फोन किया था। इसके बाद उसने प्राथमिकी में कहा था कि उसके बहनोई रहीस और उसके साथी नबी हसन ने पहले उसकी भतीजी का गला घोटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी और उसके बाद उसकी पहचान मिटाने के लिए उस पर तेजाब फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही कहा था कि भतीजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला 2016 के अपराध संख्या 0976 के रूप में दर्ज किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326क, 201, 342 और 34 के तहत दर्ज किया गया था।

3. पहले मुखबिर की भतीजी की मृत्युपूर्व घोषणा 5.12.2016 को ही दर्ज की गई थी। 5.12.2016 को दर्ज की गई मृत्युपूर्व घोषणा में कहा गया था कि फरहीन (पीड़िता) पिछले 5 से 6 महीने से अपनी बड़ी मामी सायरा के साथ डॉ. मुबारक अली की पत्नी (पहली मुखबिर रिपोर्ट का लेखक) के साथ पुलिस स्टेशन – भगतपुर जिला – कासीपुर में रह रही थी। उसने कहा था कि उसके गांव मसवानी में, उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और इसलिए उसके पिता ने उसे अपनी बड़ी मामी सायरा के साथ छोड़ दिया था ताकि वह उस लड़के से अलग हो सके जिससे वह प्यार कर रही थी। उसने तब कहा था कि 4.12.2016 को शाम लगभग 6:00 बजे उसके पिता रहीस काशीपुर में उसके मामीजी के घर आए और उसे सूचित किया कि वह उसे घर ले जाना चाहता है जहां फरहीन की शादी के उद्देश्य से कुछ लोग उससे मिलने आ रहे थे। इसके बाद उसने अपने मृत्युपूर्व बयान में कहा था कि उसे नहीं पता कि उसके पिता रहीस उसे कहां ले गए थे। उसने यह भी उल्लेख किया था कि उसके साथ एक और व्यक्ति था और वे दोनों उसे रात के लगभग 11 और 12 बजे एक जंगल में ले गए और उन्होंने पहले उसका गला घोट दिया और उसके बाद उसके चेहरे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर कुछ डाल दिया और उस पर आग लगा दी। उसे वहां पड़ा देख किसी ने 108 पर पुलिस को फोन किया और एंबुलेंस आकर उसे अस्पताल ले गई। उसने यह भी कहा था कि अस्पताल में उसकी मामी सायरा, उसकी मां मुबारक अली वहां थीं, लेकिन उसके पिता नहीं आए थे।

4. इसके बाद पहले मुखबिर श्री अहमद अली द्वारा प्रदान किए गए कपड़ों को भी पुलिस की हिरासत में रखा गया और मेमो को एक्जिबिट केए2 के रूप में गिना गया। पीड़ित की एक बंद बोतल और कुर्ता भी बरामद किया गया और उसे प्रदर्शनी केए-13 के रूप में रखा गया। जब पीड़िता को जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (एम्स) दिल्ली भेजा गया तो एक एडमिट कार्ड तैयार किया गया, जो रिकवरी का भी एक हिस्सा है। इसके बाद जब 23.12.2016 को दोपहर 2:30 बजे जांच के बाद पीड़ित की मृत्यु हो गई, तो शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया, जो 24.12.2016 को दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया गया था।

5. जांच पूरी होने पर, अपीलकर्ता रईस उर्फ रहीसा और नबी हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित 326 क और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप तय किए गए। मुकदमे के दौरान नबी हसन की मृत्यु हो गई थी और फैसले के समय वह जीवित नहीं थे और इसलिए, एकमात्र अपीलकर्ता रईस के खिलाफ मुकदमा जारी था और जब उन्हें दोषी ठहराया गया था, तो उनके द्वारा वर्तमान आपराधिक अपील दायर की गई थी।

6. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा 13 गवाहों से पूछताछ की गई।

7. पी.डब्ल्यू.-1 पहला मुखबिर अहमद अली था जिसने कहा है कि 4.12.2016 को वह अपने गांव काशीपुर से चिल्किया टांडा नामक एक गांव में गया था और जब वह दूर था तो पीड़ित/मृतक उसकी भतीजी कहीं चली गई थी।

5.12.2016 को, उसे एक फोन आया कि फरहीन, उसकी भतीजी, नजीबाबाद सरकारी अस्पताल में है और इसलिए,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वह अपने भाई मुबारक के साथ उस अस्पताल में पहुंचा और वहां उसने पाया कि फरहीन को जला दिया गया था और वह बोलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वह अच्छी स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर ने उसे दिल्ली ले जाने की सिफारिश की थी और उसने कहा है कि उसका भाई मुबारक अली उसे दिल्ली ले गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इस तथ्य से स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि उनके बहनोई रईस और उनके साथी नबी हसन दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन्हें ले गए थे और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी। जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो पीडब्ल्यू-1 को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उनसे जिरह की और कहा कि हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके भाई मुबारक अली द्वारा लिखी गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा गया था और उन्होंने केवल उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अन्य सभी स्थानों पर जहां उनके हस्ताक्षर थे, उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उन्हें लगाने के बाद, उन्होंने दस्तावेज की सामग्री को पढ़ा था।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों पर उन्हें पढ़कर सुनाए जाने पर, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई बयान दर्ज नहीं किया था जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि जब वह अस्पताल पहुंचे थे तो पीड़ित बोलने की स्थिति में था। यह सुझाव दिए जाने पर कि वह अपने ही बहनोई को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा था कि यह एक गलत तथ्य है। बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर, उन्होंने कहा था कि वह नबी हसन को नहीं पहचानते हैं। अभियोजन पक्ष से अपनी जिरह में उन्होंने जो कहा था, वह उन्होंने बचाव पक्ष द्वारा की गई अपनी जिरह में भी दोहराया था।

9. पी.डब्ल्यू.-2 मुबारक अली थे, जो पी.डब्ल्यू.-1 के भाई थे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब वह 4.12.2016 को अपने खेतों में काम कर रहे थे, तब उनकी भतीजी उन्हें बताए बिना उनके घर से चली गई थी। वह यह कहकर अपना स्टेट-इन-चीफ भी दर्ज कराता है कि 5.12.2016 को सुबह 7:00 बजे उसे इस तथ्य के बारे में जानकारी मिली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि फरहीन को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे इस तरह से जला दिया गया था कि उसका चेहरा भी गंभीर रूप से जल गया था और वह बोल नहीं सकती थी और इसलिए उसे आगे के इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया था। वह उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले गए थे, जहां 23.12.2016 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इस बात से सिरे से इनकार किया कि उनके बहनोई रईस और उनके साथी नबी हसन ने हत्या की थी। उसे शत्रुतापूर्ण भी घोषित कर दिया गया। राज्य के वकील ने उससे जिरह की और जब धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दिया। दिखाए जाने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो उसमें दर्ज की गई थी। उन्होंने इस तथ्य से भी इनकार किया था कि उनके बहनोई रईस ने 4.12.2016 को पीड़िता को ले लिया था। जब बचाव पक्ष के वकील ने उनसे जिरह की, तो उन्होंने वही दोहराया जो उन्होंने अभियोजन पक्ष से जिरह में दोहराया था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो पीड़ित बोल नहीं सका।

10. पी.डब्ल्यू-3, श्रीमती फातिमा, मृतक की मां हैं। उसने यह भी कहा था कि फरहीन उसकी बेटी थी और वह लगभग एक सप्ताह पहले मुबारक अली और अहमद अली के घर गई थी। अहमद अली ने 5.12.2016 को उसे सूचित किया था कि किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंका था और पीड़िता बिजनौर के अस्पताल में थी और उसके बाद, उसने कहा था कि उसका भाई पीड़िता को दिल्ली ले गया था। इस स्तर पर, उसे शत्रुतापूर्ण भी घोषित कर दिया गया था। अपनी जिरह में, वह उस प्रेम संबंध के बारे में कहानी से इनकार करती है जो मृतक ने कथित तौर पर अपने गांव के एक लड़के के साथ किया था। उसने यह भी कहा था कि उसने वास्तव में अपनी बेटी को अपने भाई के घर नहीं भेजा था। उसने यह भी कहा था कि उसका पति रईस 4.12.2016 को अपनी बेटी को लेने नहीं गया था और इसलिए, उसने इस तथ्य से भी इनकार किया था कि उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। उन्होंने धारा 161 आपराधिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान से भी इनकार किया। उसने यह भी कहा था कि वह नबी हसन को नहीं जानती जो अदालत में मौजूद थे। उन्होंने इस जानकारी से भी इनकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसने लिखी थी।

11. पी.डब्ल्यू.-4, श्रीमती सायरा, मुबारक अली (पी.डब्ल्यू.-3 के भाई) की पत्नी हैं। पीडब्ल्यू -3 और उसके पति के साथ अपने रिश्ते का परिचय देने के बाद, वह कहती है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी कि रईस अपनी बेटी से नाराज था। हालांकि, उसने कहा कि वह पहले भी उसके घर आया था और उसी तारीख को वह अपनी बेटी को अपने साथ ले गया था और उसके बाद, वह अपने पति और देवर (नन्हे) के साथ नजीबाबाद अस्पताल गई थी और उसने यह भी कहा था कि पीड़िता उस दिन बोल नहीं सकती थी और उसने उन्हें कोई जानकारी भी नहीं दी थी। उसे शत्रुतापूर्ण भी घोषित कर दिया गया। अपनी जिरह में, उसने धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान से इनकार किया। और इस तथ्य को दोहराया कि पीड़ित बोलने की स्थिति में नहीं थी।

12. पीडब्ल्यू-6 डॉ. सूरज ओहल, सीनियर कंसल्टेंट फॉरेंसिक विभाग, एम्स, दिल्ली हैं। उन्होंने 24.12.2016 को दोपहर 12:45 बजे मृतक का पोस्टमार्टम किया था। इसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित कर दिया था।

13. पी.डब्ल्यू.-7 डॉ. शील कुमार गौतम हैं, जो सीएचसी नजीबाबाद जिला बिजनौर में डॉक्टर थे, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस व्यक्ति की देखभाल की थी जिसे एम्बुलेंस 108 द्वारा लाया गया था। उसने कहा था कि उसने उसे बिजनौर के अस्पताल में रेफर कर दिया था। उसने अपनी जिरह में कहा था कि उसे यह नहीं पता था कि पीड़िता किस जगह की थी। चेहरा, छाती और गर्दन जल गई थी। वह बोलने की स्थिति में नहीं थी और इसलिए वह यह नहीं बता सकी कि वह कहां से आई है। उसे कौन लाया था, यह भी पता नहीं चल पाया है। मरने की घोषणा पर उसका नाम कैसे लिखा गया था, यह उसे नहीं पता था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने दुर्घटना रजिस्टर में चोटों का विवरण दिया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. पी.डब्ल्यू.-8 रमेश चंद्र, नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जिला बिजनौर था, जिनकी उपस्थिति में 5.12.2016 को पीड़ित कुमारी फरहीन की मृत्यु घोषणा दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा था कि वह अस्पताल के बर्न वार्ड में पहुंचे थे जहां आपात स्थिति में काम कर रहे डॉक्टर मौजूद थे और उन्होंने अपना प्रमाण पत्र दिया था कि पीड़िता अपना बयान दर्ज कराने के लिए पर्याप्त स्वस्थ थी। दोपहर 2:15 बजे, उन्होंने बयान की रिकॉर्डिंग के साथ शुरुआत की थी और दोपहर 2:30 बजे बयान की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। मरने की घोषणा को प्रदर्शनी का-8 के रूप में गिना गया था।

15. हालांकि, अपनी जिरह में, नायब तहसीलदार, पी.डब्ल्यू.-8 ने कहा था कि जब बयान दर्ज किया जा रहा था तो पीड़ित के बगल में एक महिला और एक पुरुष बैठे थे, जिन्होंने उसे बताया था कि वे पीड़ित के रिश्तेदार हैं। जब बयान दर्ज करने का काम शुरू हुआ तो उन्होंने उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था। हालांकि, चूंकि पीड़िता का चेहरा और मुंह पूरी तरह से जल गया था, इसलिए उसे पहचाना नहीं जा सका। साथ ही जब यह निश्चित हो गया कि वह बोल नहीं सकती है तो उसके बगल में बैठी महिला को उसके द्वारा बुलाया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि महिला को अंदर बुलाने का एक और कारण था क्योंकि पीड़िता जो कुछ भी कह रही थी वह समझ में नहीं आ रही थी।

16. इसके बाद कमरे में प्रवेश करने वाली महिला ने पीड़िता को बोलते हुए सुना और उसने पी.डब्ल्यू.-8 को बताया कि वह क्या बोल रही थी। अंदर आने वाली महिला ने पी.डब्ल्यू.-8 को जो बताया उसे मृत्युपूर्व घोषणा के रूप में दर्ज किया गया था और इसे प्रदर्श का-8 के रूप में गिना गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदर्श का -8 उस रिश्तेदार द्वारा दिए गए बयान पर तैयार किया गया था, जिसे कमरे के अंदर आने की अनुमति दी गई थी।

17. पी.डब्ल्यू.-9 राम सरन है जो एम्बुलेंस 108 का एम्बुलेंस चालक था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लड़की बोल नहीं सकती है। उसने अपना नाम भी नहीं बताया था। उसने निश्चित रूप से अपने पिता और उसके सहयोगी के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नाम नहीं बताए थे। तबीयत खराब होने की वजह से उसे बिजनौर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। चालक को भी शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। जिरह में, चालक P.W.-9 उस बयान पर अड़ा रहा जो उसने मुख्य परीक्षा में दिया था।

18. पी.डब्ल्यू.-10 जांच अधिकारी थे। उन्होंने कहा था कि 28.12.2016 को वह पुलिस स्टेशन नजीबाबाद में तैनात थे और उन्होंने मामले की जांच की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा था कि ड्राइवर राम सरन का बयान दर्ज करने के बाद, वह अपनी ओर इशारा करते हुए, उस स्थान पर गए थे, जहां घटना हुई थी और उन्हें प्रदान की गई सहायता से उन्होंने साइट प्लान तैयार किया था। उसने 9.1.2017 को आरोपी को रिमांड पर लिया था।

19. 24.1.2017 को, उन्होंने पी.डब्ल्यू.-1 अहमद अली का बयान दर्ज किया था और पी.डब्ल्यू.-3 फातिमा का बयान उनके द्वारा 25.1.2017 को दर्ज किया गया था। उन्होंने कॉल डिटेल् रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के टेलीफोन नंबर लिए थे। यह रिपोर्ट उन्हें 3.2.2017 को प्राप्त हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि कॉल डिटेल् रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की मौजूदगी घटना स्थल पर पाई गई थी। उन्होंने कहा था कि 9756428205 और 9719696796 टेलीफोन नंबर आरोपी रईस के टेलीफोन थे और घटना के समय उनका इस्तेमाल किया गया था। वह अपनी जिरह में दृढ़ रहे।

20. पी.डब्ल्यू.-11 डॉ. के.के. सिंह थे और उन्होंने कहा था कि वह प्रासंगिक तिथि यानी 5.12.2016 को आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी थे और उन्होंने कहा था कि कुमारी फरहीन की मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए, नायब तहसीलदार, बिजनौर रमेश चंद्र दोपहर 2:15 बजे आए थे और उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने प्रमाण पत्र दिया था कि पीड़िता अपना बयान दर्ज कराने की स्थिति में थी। इसके बाद नायब तहसीलदार ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा है कि बयान दर्ज करने के बाद दोपहर 2:30 बजे उन्होंने फरहीन को देखा था और पाया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



था कि वह मानसिक स्थिति में थी। तब उनसे यह पूछे जाने पर कि क्या वह बयान दर्ज किए जाने के समय मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि वह उस समय उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने प्रमाण पत्र में यह भी नहीं बताया था कि पीड़ित पुरुष है या महिला। उन्होंने प्रमाण पत्र पर समय और स्थान भी नहीं बताया था। किस आधार पर उसने कहा था कि वह एक फिट मानसिक स्थिति में थी, उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि उसने यह प्रमाण पत्र कैसे दिया।

21. पी.डब्ल्यू.-12 रोहतास सिंह चौधरी थे और उन्होंने कहा था कि 5.12.2016 को वह नजीबाबाद में तैनात उप निरीक्षक थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मृत्युपूर्व बयान नायब तहसीलदार रमेश चंद्र द्वारा दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने केस डायरी में सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे। जब आरोपी ने उसे पीड़िता के कपड़े और तेजाब की बोतल के निपटान के तरीके के बारे में बताया था तो वह आरोपी के इशारा पर उन्हें बरामद कराने गया था। इसके बाद उन्होंने बताया था कि जब तक जांच उनके हाथ में नहीं थी, तब तक उन्होंने जांच जारी रखी थी।

22. पी.डब्ल्यू.-13 डॉ. अंतरिक्षा कुमार थे। उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में संबंधित तारीख पर थे, जहां पीड़िता को उसके चाचा मुबारक अली ने भर्ती कराया था। उन्होंने कहा था कि घायल बोलने के लिए फिट स्थिति में थे और उसके बाद उन्होंने चोटों के बारे में उल्लेख किया था। उन्होंने 7.12.2017 को नबी हसन के निधन की पुष्टि की थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी अपीलकर्ता रईस का बयान। इसे 7.3.2019 और उसके बाद 18.11.2019 को दर्ज किया गया था।

23. मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 3, बिजनौर द्वारा निर्णय और आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा उन्होंने 18.2.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 326क/34, 342 और 201 के तहत आरोपी अपीलकर्ता रईस अहमद को दोषी ठहराया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



24. दिनांक 19.2.2020 के आदेश द्वारा सजा सुनाई गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 क के साथ पठित धारा 302 के तहत। अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 40,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह प्रावधान किया गया था कि यदि वह जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे दो महीने की और कैद काटनी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई थी। रईस अहमद को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत 7 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना जमा न करने पर एक महीने की और कैद की व्यवस्था की गई। जुर्माने का आधा हिस्सा मृतक की मां को जाना था।

25. जब अपील पर बहस की गई, तो अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि:-

I. पी.डब्ल्यू.-1, पहला मुखबिर, पी.डब्ल्यू.-2 पहले मुखबिर का भाई, पी.डब्ल्यू.-3 श्रीमती फातिमा, मुबारक अली पी.डब्ल्यू.-2 की पत्नी और पीड़िता की मां श्रीमती सायरा ने मुकदमे में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था और इसलिए, अपीलकर्ता को दंडित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास बहुत कम सबूत उपलब्ध थे।

II. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष 1, 2, 3, 4 और ड्राइवर पी.डब्ल्यू.-9, राम सरन भी मुकदमे गए थे, तो एकमात्र सबूत, यानी मृत्युपूर्व घोषणा का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए था।

III. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अभी भी आगे प्रस्तुत किया कि डॉ. शील कुमार गौतम पी.डब्ल्यू.-7, जिन्होंने शुरू में पीड़िता की देखभाल की थी, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पीड़ित बोलने की स्थिति में नहीं थी। वास्तव में, वह यह कहने की हद तक चले गए हैं कि वह यह बताने की स्थिति में भी नहीं हैं कि वह किस स्थान की रहने वाली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हैं। उसे कौन लाया था, यह भी उसके द्वारा नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा है कि मृत्युपूर्व बयान पर पीड़िता का नाम कैसे दर्ज किया गया, यह उनके लिए एक रहस्य था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने पी.डब्ल्यू.-8 के बयान की ओर इशारा किया, जिन्होंने अपनी परीक्षा-इन-चीफ में कहा था कि आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी जो उपस्थित थे, अर्थात् पीडब्ल्यू - 11 डॉ. केके सिंह ने कहा था कि पीड़िता अपना बयान देने की स्थिति में थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी, उसने जिरह में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वह क्या बोल रही थी, यह समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसे बयान दर्ज कराने में एक महिला की सहायता लेनी पड़ी जो पीड़िता की रिश्तेदार थी। चूंकि पीड़िता स्पष्ट रूप से नहीं बोल रही थी और वह जो बोल रही थी वह समझ से बाहर था, इसलिए यह आवश्यक था कि महिला को कमरे के अंदर बुलाया जाए। उन्होंने जो कहा वह पी.डब्ल्यू.-8 नायब तहसीलदार श्री रमेश चंद्र द्वारा दर्ज किया गया था।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पी.डब्ल्यू.-8 द्वारा दर्ज किया गया बयान सीधे तौर पर पीड़ित द्वारा नहीं कहा गया था, बल्कि पीड़ित के रिश्तेदार द्वारा कहा गया था, इसे मृत्युकालिक कथन के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि 1996 एससीसी सीआरएल 31 (कांची कोमुरम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य) और 2010 (6) एससीसी 566 (पूरन चंद बनाम हरियाणा राज्य) के फैसले के अनुसार, एक मृत्युपूर्व घोषणा भले ही मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई हो, केवल सबूत का एक टुकड़ा है और यह सच्चाई का प्रमाण नहीं है। यहां तक कि मृत्युपूर्व घोषणा को भी अदालत की जांच से गुजरना पड़ता है। 2010 (6) एससीसी 566 (पूरन चंद बनाम हरियाणा राज्य) पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने फैसले के पैराग्राफ संख्या 15 पर भरोसा किया और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कहा कि अदालत द्वारा अपने सही परिप्रेक्ष्य में सबूतों पर विचार किया जाना चाहिए। चूंकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 पर भरोसा किया था, इसलिए इसे यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: –

15. नीचे की अदालतों को बेहद सावधान रहना होगा जब वे एक मरणासन्न घोषणा से निपटते हैं क्योंकि उसका निर्माता जिरह के लिए उपलब्ध नहीं है जो आरोपी व्यक्ति के लिए एक बड़ी कठिनाई पैदा करता है। मरने वाली घोषणा पर भरोसा करने में एक यांत्रिक दृष्टिकोण सिर्फ इसलिए कि यह है बेहद खतरनाक है। अदालत को यह पता लगाने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टि से एक मृत्युकालिक कथन की जांच करनी होगी कि क्या मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक, सच्ची है, सचेत मन की स्थिति में की गई है और उपस्थित रिश्तेदारों या जांच एजेंसी से प्रभावित हुए बिना है, जो जांच की सफलता में रुचि रखते हैं या जो मृत्युपूर्व घोषणा दर्ज करते समय लापरवाही कर सकते हैं।

यह समझाने के लिए कि मृत्युकालिक कथन का आकलन कैसे किया जाना है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने एआईआर 1958 एससी 22 (खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य) पर भरोसा किया। उन्होंने फैसले के पैराग्राफ संख्या 16–17 पर भरोसा किया और उन्हें यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: –

16. साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में तय किए गए मामलों की समीक्षा पर, हम मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की राय से सहमत होकर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, (1) कि इसे कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक मृत्युपूर्व घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है जब तक कि यह न हो पुष्टि की जाती है; (2) कि प्रत्येक मामले को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिनमें मृत्यु की घोषणा की गई थी; (3) कि यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक मरणासन्न घोषणा सबूत के अन्य टुकड़ों की तुलना में एक कमजोर प्रकार का सबूत है; (4) कि एक मरणासन्न घोषणा साक्ष्य के एक अन्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



टुकड़े के समान स्तर पर खड़ी होती है और इसे आसपास की परिस्थितियों के प्रकाश में और साक्ष्य के वजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए; (5) कि एक मृत्युपूर्व घोषणा जो एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से दर्ज की गई है, अर्थात्, प्रश्नों और उत्तरों के रूप में, और, जहां तक संभव हो, घोषणा के निर्माता के शब्दों में, एक मरणासन्न घोषणा की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर खड़ा है जो मौखिक गवाही पर निर्भर करता है जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी कमजोरियों से पीड़ित हो सकता है, तथा (6) कि एक मरणासन्न घोषणा की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, अदालत को परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि मरने वाले व्यक्ति के अवलोकन के अवसर की तरह, उदाहरण के लिए, यदि अपराध रात में किया गया था तो क्या पर्याप्त प्रकाश था; क्या बताए गए तथ्यों को याद रखने की व्यक्ति की क्षमता, उस समय क्षीण नहीं हुई थी जब वह बयान दे रहा था, उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों से; कि यह कथन पूरे समय सुसंगत रहा है यदि उसके पास आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा एक मरणासन्न घोषणा करने के कई अवसर थे; और यह कि बयान जल्द से जल्द अवसर पर दिया गया था और इच्छुक पार्टियों द्वारा ट्यूशन का परिणाम नहीं था।

17. इसलिए, विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, एक मृत्युपूर्व घोषणा को बहुत बारीकी से जांच के अधीन किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बयान अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया गया है, जिनके पास जिरह द्वारा बयान की सत्यता का परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन एक बार, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मृत्युपूर्व घोषणा मृत्यु की परिस्थितियों और पीड़ित के हमलावरों के बारे में सत्य संस्करण थी, आगे पुष्टि का कोई सवाल ही नहीं है। यदि, दूसरी ओर, अदालत, अपने सभी पहलुओं में मृत्युपूर्व घोषणा की जांच करने और इसकी सत्यता का परीक्षण करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह अपने आप में विश्वसनीय नहीं है, और यह कि यह एक दुर्बलता से ग्रस्त है, तो, पुष्टि के बिना यह दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है। इस प्रकार, पुष्टि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की आवश्यकता साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में एक मरने वाली घोषणा की किसी भी अंतर्निहित कमजोरी से उत्पन्न नहीं होती है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट किए गए मामलों में आयोजित किया गया है, बल्कि इस तथ्य से कि अदालत, किसी दिए गए मामले में, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वह विशेष मृत्यु घोषणा ऊपर उल्लिखित दुर्बलताओं से मुक्त नहीं थी या ऐसी अन्य कमजोरियों से मुक्त नहीं थी जो उस मामले में साक्ष्य में प्रकट की जा सकती हैं।

एक अन्य निर्णय जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह बताने के प्रयोजनों के लिए भरोसा किया कि एक मृत्युपूर्व घोषणा का साक्ष्य के रूप में मूल्यांकन कैसे किया जाना है, वह था 2003 (11) एससीसी 527 (सुचंद पाल बनाम फनी पाल और अन्य) और इस निर्णय से अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने पैराग्राफ संख्या 9 पर भरोसा किया, जिसे यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

9. ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के संस्करण की अस्वीकार्यता को उजागर करते हुए बचाव पक्ष के संस्करण को खारिज कर दिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गोली आंगन में करीब से बनाई गई थी। यह दलील अभियोजन पक्ष द्वारा बहस के चरण में ली गई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को इस तरह से पढ़ने की कोशिश की गई थी ताकि नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य असंगत न लगें। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम को अस्वीकार करने में सही था। यह कानून में एक स्थापित स्थिति है कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप के संस्करण को काफी हद तक साबित करके सफल हो सकता है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और बचाव पक्ष के मामले में कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता है। अदालत अपने दम पर अभियोजन पक्ष के लिए एक नया मामला नहीं बना सकती है और उस आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती है। केवल जब साक्ष्य पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है और मामले के आधार को नहीं बदला जाता है, तो इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य को बचाव पक्ष के इस कथन के अनुरूप देखा कि मृतक को करीब से गोली लगी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



थी और मुखबिर पक्ष और आरोपी के बीच हाथापाई में उसे गलती से गोली मार दी गई थी। मृत्युपूर्व घोषणा की स्वीकार्यता पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने इसे सही ढंग से खारिज कर दिया है। मृतक द्वारा की गई घोषणा स्वैच्छिक नहीं थी और वास्तव में, जवाब उसके द्वारा नहीं दिए गए थे और यह उसका पति था जो जवाब दे रहा था। घायलों की इस तरह की प्रकृति और प्रतिक्रिया के तरीके को किसी भी तरह से उसकी मृत्यु के बयान के स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, भले ही वह याकूब की आवाज सुनाई दे दी हो। अभियोजन पक्ष का रुख जिसे उन्होंने यह कहकर स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह आरोपी था जिसने बंदूक चलाई थी, स्थिति में सुधार नहीं करता है। शब्द के सही अर्थों में या कानूनी भाषा में मृतक द्वारा दिए गए बयान को मृत्युपूर्व घोषणा नहीं कहा जा सकता है। स्वीकार की गई शत्रुता और तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, आरोपी को शामिल करने का स्वाभाविक प्रयास किया गया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सबूतों को स्वीकार करने के योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने (2024) 3 एससीसी 481 (राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) पर भी भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को कैसे देखा जाना चाहिए।

IV. इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एआईआर 1984 एससी 1622 में रिपोर्ट किए गए शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले के अनुसार कि यदि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत प्रश्न पूछते समय आरोपी के सामने कोई विशेष परिस्थिति नहीं रखी जाती है। तब उस परिस्थिति को विचार के क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है क्योंकि आरोपी के पास परिस्थिति को समझाने का कोई अवसर नहीं होगा।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विशेष रूप से एआईआर 1984 एससी 1622 में रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ संख्या 142 और 144 पर भरोसा किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



142. उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा ऊपर उल्लिखित और उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा की गई कुछ परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण दोष है, अर्थात्, परिस्थितियां संख्या 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16 और 17। चूंकि इन परिस्थितियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के बयान में नहीं रखा गया था, इसलिए उन्हें पूरी तरह से विचार से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता के पास उन्हें समझाने का कोई मौका नहीं था। यह इस न्यायालय द्वारा 1953 से लगातार आयोजित किया गया है, जहां हाते सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य एआईआर 1953 एससी 468 के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि किसी भी परिस्थिति के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत किसी आरोपी की जांच नहीं की गई थी, उसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के बाद से, इस न्यायालय के अधिकारियों ने समान रूप से यह विचार व्यक्त किया है कि जब तक किसी अभियुक्त के खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थिति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 या धारा 313 के तहत उसकी परीक्षा में नहीं रखा जाता है, तब तक उसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है। शामू बालू चौगुले बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एससीसी 438: (एआईआर 1976 एससी 557) में इस न्यायालय ने इस प्रकार माना:

"तथ्य यह है कि अपीलकर्ता को फरार बताया गया था, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत नहीं रखा गया था, उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।

144. हमारे लिए इस बिंदु पर अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रश्न अब इस न्यायालय के कई निर्णयों से समाप्त हो गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, जिन परिस्थितियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता की परीक्षा में नहीं रखा गया था, उन्हें पूरी तरह से विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अभी भी 2013 (12) एससीसी 406 (सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य) पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी व्यक्तियों की जांच करने का उद्देश्य है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा करना था। चूंकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की सामग्री पर भरोसा किया। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता। यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

313. अभियुक्त की जांच करने की शक्ति। (1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय

(क) किसी भी स्तर पर, पूर्व चेतावनी के बिना अभियुक्त उससे ऐसे प्रश्न रख सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे;

(ख) अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ किए जाने के बाद और उसके बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, मामले पर आम तौर पर उससे पूछताछ करेगा:

बशर्ते कि एक समन मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया है, वह खंड (ख) के तहत उसकी परीक्षा को भी समाप्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त की जांच करते समय उसे कोई शपथ नहीं दी जाएगी।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करके या उनके झूठे उत्तर देकर स्वयं को दण्ड के भागी नहीं बनाएगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या विचारण में ध्यान में रखा जा सकता है, और किसी अन्य अपराध में उसके पक्ष में या उसके खिलाफ साक्ष्य में रखा जा सकता है, या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है, जो ऐसे उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(5) न्यायालय अभियुक्त के समक्ष पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की सहायता ले सकता है और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

V. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि यदि धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बयान। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में, रिश्तेदार ने जो कुछ भी कहा था, उसके आधार पर बयान को रिकॉर्ड किया गया था, तो अभियुक्त के सामने कभी नहीं रखा गया था और इसलिए, रिश्तेदार ने मृत्युपूर्व घोषणा में जो कुछ भी उल्लेख किया था, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता था। उन्होंने फिर भी एआईआर 2015 एससी 310 (नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य) पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान आरोपी को भौतिक साक्ष्य नहीं देना धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के जनादेश का पालन न करने के बराबर है। ट्रायल कोर्ट द्वारा। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एआईआर ऑनलाइन 2023 एससी 766 (सुनील बनाम दिल्ली राज्य राज्य) और एआईआर 2025 एससी 308 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), एआईआर 2023 एससी 5221 (इंद्रकुंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) और एआईआर 2024 एससी (सीआरआई.) 437 (नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य) पर भी भरोसा किया।

VI. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि यदि मृत्युपूर्व घोषणा का अवलोकन किया जाता है तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि बयान दर्ज करने वाले नायब तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पीड़ित बोलने की स्थिति में नहीं था और जो बयान दर्ज किए गए थे, वे मृतक के रिश्तेदार द्वारा कही गई बातों के आधार पर दर्ज किए गए थे। दिनांक 5.12.2016 की मृत्युपूर्व घोषणा को भी पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने का समय दिनांक 05-12-2016 मृत्यु पूर्व बयान कु० फरहीन कु० फरहीन पुत्री रहीस उम्र लगभग 17 साल निवासी ग्राम कच्छवासी, जिला रामपुर, थाना स्वार, निवासी नई बस्ती विजयनगर, काशीपुर, उत्तराखण्ड ने बहलफ बयान दिया कि- मैं पाँच छः महीने से अपनी बड़ी मामी सायरा पत्नी डा० मुबारक अली थाना भगतपुर काशीपुर में रह रही थी। मेरा कच्छवासी में एक लड़के से प्यार का चक्कर चल रहा था, इस कारण मेरे अब्बा ने मुझे चार-पाँच महीने पहले मुझे मेरी बड़ी मामी सायरा के घर छोड़ दिया था, जिससे कि मेरा उस लड़के से प्यार का चक्कर छूट जायें। कल दिनांक 04-12-16 को शाम 6:00 बजे मेरे पिता रहीस मेरे मामी के घर काशीपुर आये तथा मुझे मेरी मामी के घर से यह कहकर लेकर आये कि मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। इसका निकाह करेंगे। इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इसके बाद मुझे पता नहीं कि मेरा पिता रहीस मुझे कहाँ लेकर गया, उसके साथ एक अन्य आदमी भी था। मेरे पिता ने जंगल में ले जाकर रात्रि 11-12 बजे के लगभग मेरा गला घोंटा तथा मुझे मरा हुआ समझकर आग लगा दी, जिससे मैं जल गयी। उसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना की। पुलिस ने ने 108 एम्बुलेंस मंगाकर मुझे समीपुर अस्पताल भिजवाया वहाँ मुझे जिला चिकित्सालय बिजनौर में रेफर कर दिया है। यहाँ अस्पताल में मेरी बड़ी मामी सायरा व मेरे मामा डा० मुबारक अली आ गये हैं। मेरा पिता नहीं आया है। बयान सुनकर तस्दीक किया। बयान समाप्त करने का समय 2:30 पी०एम०।

नि० अं०

अपठित

नि० अं० दाया

कु० फरहीन पुत्री रहीस

सत्य -- प्रतिलिपि"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि यदि कोई नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज की गई मृत्युपूर्व घोषणा को देखता है, तो नायब तहसीलदार की जिरह को देखते हुए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता बोल नहीं सकती थी और इसलिए, यह समझने के लिए कि वह क्या बोल रही थी, पीड़िता के रिश्तेदार को कमरे के अंदर बुलाया गया था और रिश्तेदार ने जो कहा उसके बाद दर्ज किया गया था। नायब तहसीलदार की जिरह के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"जब मैं बयान लेने गया वहाँ पर लड़की उर्फ फरहीन के पास एक महिला व एक पुरुष बैठे थे। जो फरहीन को अपना रिश्तेदार बता रहे थे। मैंने जब बयान लिखना शुरू किया था तब उन्हें कक्ष से बाहर कर दिया था। कु० फरहीन का चेहरा व सीना पूरी तरह से जला हुआ था। पहचान में भी नहीं आ रही थी, करहा रही थी, बोल रही थी स्पष्ट नहीं बोल रही थी जो बोल रही थी वह स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उस महिला को बुलवाया जो उसकी रिश्तेदार थी, उसके साथ थी और उस महिला से पूछा कि यह क्या कह रही है, जो उस महिला ने बताया था, वह मैंने प्रदर्शक का -8 में लिख दिया था। प्रदर्शक का -8 मैंने फरहीन की रिश्तेदार के बताने व बोलने पर लिखा था क्योंकि फरहीन ठीक से नहीं बोल पा रही थी"

इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि मृत्युपूर्व घोषणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बेकार दस्तावेज था कि सबसे पहले यह पीड़ित के बोलने पर नायब तहसीलदार द्वारा सीधे दर्ज नहीं किया गया था और दूसरी बात यह है कि अभियोजन पक्ष उसे गवाह के कठघरे में लाने में सक्षम बनाने के लिए रिश्तेदार के नाम का भी खुलासा नहीं किया गया था।

VII. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के कारण मामला और भी संदिग्ध हो जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू.-1 में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह उसके पिता और नबी हसन थे जो उसे

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसके मामा के स्थान से ले गए थे, लेकिन मृत्युपूर्व घोषणा में अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख किया गया था लेकिन नबी हसन के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था।

VIII. अपीलकर्ता ने आगे कहा कि एक और परिस्थिति थी जो यह दिखाती है कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया था और वह यह थी कि मृत्युपूर्व घोषणा को 5.12.2016 को रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि, 23.12.2016 को मृतक की मृत्यु हो गई और एम्स के डॉक्टर ने भी बयान दिया था कि वह बाद में बोलने में सक्षम थी। हालांकि, बाद में इस तथ्य के बावजूद कोई मृत्युपूर्व घोषणा दर्ज नहीं की गई कि मृतक लगभग 18 दिनों तक जीवित रहा।

IX. विद्वान वकील ने आगे कहा कि जब रिश्तेदार द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पीड़ितों का बयान दर्ज किया जा रहा था, तो पी.डब्ल्यू.-8 द्वारा यह उल्लेख किया जाना चाहिए था कि रिश्तेदार कौन था और वास्तव में उसका नाम क्या था। इस जानकारी के अभाव में किसी भी रिश्तेदार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जा सका और बयानों को साबित करने के लिए अदालत में उसका कोई बयान दर्ज नहीं किया जा सका, जैसा कि उसके डिक्टेशन पर दर्ज किया गया था।

26. हालांकि, विद्वान एजीए ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि मृत्युपूर्व घोषणा को एक रिकॉर्ड किए गए बयान के रूप में माना जाना चाहिए जो पवित्र था और कोई भी अदालत इसे हल्के में नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यह साक्ष्य का एक ठोस टुकड़ा था जिसे इस तरह से पढ़ा जाना था और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था और वास्तव में, उन्होंने यह कहने की हद तक चला गया था कि भले ही मृत्युपूर्व घोषणा पीड़ित के करीबी रिश्तेदार के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी, फिर भी मृत्युपूर्व घोषणा पवित्र थी और इस पर विश्वास किया जाना चाहिए था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



27. विद्वान एजीए ने यह भी प्रस्तुत किया है कि भले ही गवाह मुकर गए हों, फिर भी परिस्थितियां ऐसी थीं, जो यह इंगित करती थीं कि अपीलकर्ता रईस अहमद ने अपने सहयोगियों की मदद से पीड़िता का गला घोट दिया था और उसके बाद, उस पर तेजाब फेंक दिया था और परिस्थितियां ऐसी थीं जिन्हें हल्के ढंग से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

28. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एम.जे. अख्तर और राज्य के लिए श्री अमित सिन्हा की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.एम. जैदी को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाह जिन्होंने मामले की शुरुआत की थी और जिनके लिखित और मौखिक बयान पर पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, वे मुकर गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में की गई जिरह के साथ-साथ इन शत्रुतापूर्ण गवाहों के बचाव में भी कोई खास फल नहीं निकला। इस प्रकार, हम पाते हैं कि एकमात्र आधार जिस पर दोषसिद्धि की जा सकती थी, वह यह था कि पीड़ित/मृतक की मृत्युपूर्व घोषणा की गई थी। हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि मृत्युपूर्व घोषणा 5.12.2016 को दर्ज की गई थी, पी.डब्ल्यू-11, डॉ. केके सिंह ने एक बयान दिया था कि पीड़िता बोलने की स्थिति में थी।

29. हालांकि, यदि हम मृत्युपूर्व घोषणा पर पीडब्ल्यू 11 के दर्ज बयान को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उसने यंत्रवत् कहा था कि पीड़िता अपना बयान देने की स्थिति में थी। उन्होंने यह नहीं बताया था कि किसका बयान दर्ज किया जाना था और उन्होंने यह भी नहीं बताया था कि पीड़ित पुरुष था या महिला। मृत्युपूर्व घोषणा में समय और स्थान का भी उल्लेख नहीं किया गया था। किस आधार पर उन्होंने इस तथ्य के संबंध में अपना बयान दिया था कि पीड़िता अपना बयान देने की स्थिति में थी, यह भी दर्ज नहीं किया गया था। इन सभी तथ्यों को चूक के रूप में माना जा सकता था और मृत्युपूर्व घोषणा पर अभी भी विश्वास किया जा सकता था। हालांकि, जब हमें पीडब्ल्यू-8 के बयान के माध्यम से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिया गया तो हमने पाया कि पीडब्ल्यू-8 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पीड़िता बिल्कुल भी बोलने में सक्षम नहीं थी और इसलिए, उसके एक रिश्तेदार को कमरे के बाहर से बुलाया गया था और रिश्तेदार ने पहले पीड़िता की बात सुनी और उसके बाद वह पीड़िता की ओर से बोलती थी और उन बयानों को नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया था। अपने बयान में उसने स्पष्ट रूप से बताया था कि उसने रिश्तेदार का नाम दर्ज नहीं किया था और पीड़िता का रिश्तेदार के साथ क्या संबंध था। हम पाते हैं कि धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करते समय भी इस परिस्थिति को आरोपी के सामने नहीं रखा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत सवाल पूछते समय आरोपी को सूचित नहीं किया गया कि पीड़िता के एक रिश्तेदार द्वारा कही गई बातों के आधार पर मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया गया था। इस प्रकार हमारा निश्चित विचार है कि जब इस परिस्थिति को आरोपी के सामने नहीं रखा गया था तो मृत्युपूर्व घोषणा को आरोपी के खिलाफ निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूत के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।

30. इस प्रकार जब बयान स्वयं पीड़ित का दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन पीड़ित के रिश्तेदार क्या कह रहा था, के आधार पर दर्ज किया गया था, तो हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए मृत्यु घोषणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही, हमारा यह भी विचार है कि अगर पी.डब्ल्यू-8 नायब तहसीलदार ने मृत्युपूर्व घोषणा में कहा होता कि पीड़िता का रिश्तेदार कैसे संबंधित था और तब भी उसे प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अदालत में पेश किया जा सकता था। लेकिन इन तथ्यों/सूचनाओं के अभाव में, जब न तो संबंध और न ही रिश्तेदार का नाम ज्ञात था, अभियोजन पक्ष उसे गवाह के बक्से में नहीं बुला सका। यहां तक कि अदालत को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि पीड़िता के बयान दर्ज कराने में किसने मदद की। हमारा यह भी विचार है कि जब पीड़िता को एम्स ले जाया गया, जहां 18 दिनों के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका कोई बयान दर्ज नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया गया, उसके बाद मृत्यु घोषणा 5.12.2026 को दर्ज की गई थी। ये सभी तथ्य निश्चित रूप से यह संकेत देते हैं कि मृत्युपूर्व घोषणा, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष बहुत अधिक निर्भर था, वह एक विश्वसनीय सबूत नहीं था। वास्तव में, चूंकि इस परिस्थिति के बारे में प्रासंगिक प्रश्न कि रिश्तेदार ने पीड़ित का बयान दर्ज करवाया था, आरोपी के सामने नहीं रखा गया था, इसलिए हमारा विचार है कि मृत्युपूर्व घोषणा में जो कुछ भी कहा गया था, उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए और इसे सबूत के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए।

31. इस प्रकार, हमारा विचार है कि इस आधार पर कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जा सकता था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, बिजनौर द्वारा 2017 की धारा 3 (राज्य बनाम रईस अहमद और अन्य) में 2016 की धारा 302/34, 326क/34, 342 और 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 2016 के मामले में उत्पन्न होने वाले मामले के अपराध संख्या 120 (राज्य बनाम रईस अहमद और अन्य) द्वारा पारित निर्णय और आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, बिजनौर द्वारा धारा 302/34, 326क/34, 342 और 201 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन नजीबाबाद, जिला बिजनौर के तहत मामला अपराध संख्या 976/2016 से उत्पन्न मामले में दिनांक 19.2.2020 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता को उन आरोपों से बरी कर दिया जाता है जैसा कि उसके खिलाफ लगाए गए थे। अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता को यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

32. निर्णय समाप्त करने से पूर्व, मैं अपने शोध सहायक श्री अभिषेक वर्मा के प्रति उनके उत्कृष्ट विधिक अनुसंधान, दक्षता तथा इस निर्णय के प्रारूपण में प्रदान किए गए उनके असाधारण सहयोग के लिए अपनी सराहना अभिलिखित करना उचित समझता हूँ।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

दिनांक : 02 फ़रवरी, 2026

पी.के.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”